Sl. No.	States	Agreed Outlay
5.	Goa	1500.00
6.	Gujarat	28000.00
7.	Haryana	9310.00
8.	Himachal Pradesh	5700.00
9.	Jammu & Kashmir	@@
10.	Karnataka	23400.00
11.	Kerala	16100.00
12.	Madhya Pradesh	20075.00
13.	Maharashtra	36700.00
14.	Manipur	*
15.	Meghalaya	*
16.	Mizoram	*
17.	Nagaland	*
18.	Orissa	15000.00
19.	Punjab	*
20.	Rajasthan	22000.00
21.	Sikkim	1600.00
22.	Tamil Nadu	*
23.	Tripura	*
24.	Uttar Pradesh	46340.00
25.	West Bengal	16900.00

पाकिस्तान के साथ आतंकवादी और विध्वंसक कार्यवाहियों को रोकने के संबंध में सहमति

*34. **श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता के परचात् कुछ मुद्दों पर सहमति हो गई है तथा कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त वार्ता में पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवादी और विध्वंसक कार्यवाहियों को बढ़ावा देने को रोकने के संबंध में कोई सहमति अथवा विचारों का कोई आदान-प्रदान हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) से (घ) विदेश सचिव स्तर पर फिर से शुरू हुई बातचीत का दूसरा दौर इस्लामाबाद में 19—23 जून, 1997 को हुआ था। बातचीत के निष्कर्ष पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ था। दोनों पक्षों ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मसलों को हल करने का निर्णय लिया था: (क) विश्वासोत्पादक उपायों सहित शान्ति और सुरक्षा, (ख) जम्मू और कश्मीर, (ग) सियाचीन, (घ) तुलबुल नौवहन परियोजना, (ङ) सरक्रीक, (च) आतंकवाद और औषधियों का अवैध व्यापार, (छ) आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग, (ज) विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण संबंधों का संवर्द्धन। इन सभी मसलों का समेकित तरीके से हल निकालने के लिए उपयुक्त स्तरों पर कार्यकारी दलों सहित एक तंत्र का गठन करने के लिए भी सहमत हुए। उपरलिखित (क) और (ख) से सम्बद्ध मसलों पर विदेश सचिव स्तर पर कार्यवाही की जाएगी जो सभी कार्य दलों के कार्यों को समन्वित और कार्य में हुई प्रगति पर भी नजर रखेंगे। दोनों पक्ष एक-दूसरे के विरूद्ध विरोधी दुष्प्रचार और भड़काने वाली गतिविधियों से बचने के लिए हर संभव उपाय करने पर भी सहमत हुए।

संयुक्त वक्तव्य में भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापक, रचनात्मक और स्थायी बातचीत के आधारों का प्रावधान है। यह ऐसी रूपरेखा है जिसके अन्तर्गत विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातचीत होगी। हम इसे विश्वास, मित्रतापूर्ण और सहयोग के संबंध बनाने के उद्देश्य से पाकिस्तान को एक विशाल मंच पर जाने के अपने प्रयासों की दिशा में बढ़े हुए कदम के रूप में मानते हैं।

यद्यपि बातचीत मुख्यतः भावी चर्चाओं के लिए रूप-रेखाओं और तंत्र-रचना पर केन्द्रित रही किन्तु जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान के सक्रिय प्रोत्साहन के बारे में अपनी चिन्ताएं स्पष्ट रूप से बताई गई थीं और पाकिस्तान को जम्मू और कश्मीर के बारे में तथ्यात्मक स्थिति से फिर से अवगत कराया गया।

सूचना पाने के अधिकार को लागू किया जाना

*35. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्य सरकारों ने सूचना पाने के अधिकार को प्रयोग के तौर पर लागू किया है;

(ख) मध्य प्रदेश में उन विभागों और जिलों का ब्यौरा क्या है जहां इसे लागू किया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने भी इसे प्रयोग के तौर पर किसी विभाग में लागू किया है; और

(घ) यदि हां, तो उन विभागों के नाम क्या है?

* :Plan size not yet decided.

@@ :To be finalised between Rs. 9000 and Rs. 10000 crore.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० आर० बालासुब्रहमण्यन): (क) से (घ) बहुत सी राज्य-सरकारों, यथा मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा तथा राजस्थान की राज्य सरकारों ने यह रिपोर्ट किया है कि वे जनता को एक या अधिक क्षेत्रों से संबंधित सरकार की कार्रवाइयों और रैकार्ड संबंधी सूचना तक आबाध और आसान पहुंच मुहैया करवा रही है। मध्य प्रदेश के संबंध में यह रिपोर्ट किया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उपस्थिति-नामावली (मस्टर-रोल), गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की सूची, भूमि-रैकार्ड तथा प्रदूषण-नियंत्रण-बोर्ड जैसे क्षेत्रों में पारदर्शिता संबंधी अनुदेश लागू कर दिए गए हैं। केन्द्र सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों को पारदर्शिता के बारे में तथा अवर्गीकृत सूचना तक पहुंच के संबंध में अनुदेश जारी कर दिए हैं। इसने (केन्द्र-सरकार ने) इस प्रयोजन से दिल्ली में, जनता से परस्पर विचारशीलता, क्रियाशीलता और प्रभावशीलता वाले चुनिन्दा विभागों से सूचना और सुविधा-काउंटर खोलने के लिए भी कहा है।

Indian Offer of Inspection of Chemical Weapons

36. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item which appeared in the Times of India (New Delhi) dated the 27th June, 1997 under the caption "India throws open chemical weapons stocks for inspection"; if so, Government's reaction thereto;

(b) whether Government have taken enough safeguards to ensure that country's security is not compromised; and

(c) if so, the details thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) Yes, Sir. India is an original State Party to the Chemicals Weapons Convention which entered into force on 29th April, 1997. The convention requires States Parties to provide certain declarations within stipulated time schedules. India's declarations were made in keeping with the treaty obligations.

(b) and (c) India considers the CWC to be a model disarmament agreement and has asked the countries, that have not yet done so, to complete their ratification proceedings, in order to make the CWC genuinely universal and comprehensive. To date 95 countries, incldluing the USA and China have ratified this Treaty. Government remains fully committed to taking the necessary steps to safeguard India's security and national interest against all eventualities and Government's decision is in keeping with its commitments.

पड़ोसी देशों से संबंध मधुर बनाने हेतु वार्ता

*37. **प्रो० राम बख्श सिंह वर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान सरकार ने पड़ोसी देशों से अपने संबंध मधुर बनाने के लिए कोई वार्ता की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) पड़ोसी देशों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) से (ग) पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने के लिए बातचीत का देश-वार ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:—

पाकिस्तान:

सरकार पाकिस्तान के साथ विश्वास, मित्रता और सहयोग के संबंध स्थापित करने की इच्छुक है और द्विपक्षीय बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से बकाया मसलों को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करना चाहती है। तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री देव गौड़ा ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को भेजे गए अपने बधाई पत्र में पारस्परिक हितचिंता के मुद्दों पर उपयुक्त स्तर पर दोनों देशों के बीच व्यापक बातचीत करने का प्रस्ताव रखा था। इस पहल के परिणाम-स्वरूप नई दिल्ली में 28 से 31 मार्च, 1997 तक विदेश सचिव स्तर की बातचीत पुनः आरंभ हुई। माले में सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने 12 मई, 1997 को द्विपक्षीय बातचीत के लिए पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ